भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 4367
मंगलवार, 19 अगस्त, 2025/28 श्रावण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

गुजरात में डेयरी सहकारी विकास

†4367. श्री देवुसिंह चौहानः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात में अमूल और अन्य प्रमुख सहकारी समितियों के योगदान सहित डेयरी सहकारी समितियों की स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार ने गुजरात में डेयरी सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई नई नीति या वित्तीय सहायता शुरू की है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त पहलों का गुजरात में दूध उत्पादन और डेयरी किसानों की आय पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) पोर्टल के अनुसार, गुजरात में 15,740 डेयरी सहकारी समितियाँ कार्यशील हैं । गुजरात में एक सुविकसित डेयरी सहकारी नेटवर्क है, जिसका नेतृत्व गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड (GCMMF) (अमूल) करता है, जिसमें 18 जिला संघ और 36 लाख से ज़्यादा सदस्य शामिल हैं । वर्तमान में, गुजरात से अमूल अपने सहकारी नेटवर्क के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 250 लाख लीटर दूध का प्रापण करता है, जिससे गुजरात देश के अग्रणी दुग्ध उत्पादक राज्यों में से एक बन गया है । आज, 36 लाख किसानों के स्वामित्व वाला ब्रांड 'अमूल', 11 अरब अमेरिकी डॉलर (90,000 करोड़ रुपये) के वार्षिक ब्रांड बिक्री कारोबार के साथ, भारत की सबसे बड़ी FMCG इकाई है । अमूल को दुनिया के सबसे सशक्त खाद्य और डेयरी ब्रांड का दर्जा दिया गया है और सालाना 24 अरब पैक बिकने के साथ, यह दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रांड भी है ।

(ख) से (ग): GCMMF द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (DIDF) और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) जैसी योजनाओं के माध्यम से अवसंरचना आधुनिकीकरण, मूल्यवर्धन सुविधाओं, नस्ल सुधार, चारा विकास और क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान की है । पिछले सात वर्षों में, NPDD के अंतर्गत, गुजरात को

₹515 करोड़ के कुल परियोजना परिव्यय के साथ ₹315 करोड़ की अनुदान सहायता प्राप्त हुई है, जिसके परिणामस्वरूप 2,052 बल्क मिल्क कूलर, 4,309 स्वचालित दूध संग्रहण प्रणालियाँ और 1,000 दूध में मिलावट का पता लगाने वाली मशीनें स्थापित की गई हैं । DIDF और AHIDF के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं में प्रसंस्करण संयंत्र विस्तार, UHT लाइनें और दूध पाउडर सुविधाएँ शामिल हैं ।

इसके अलावा, गुजरात सरकार ने 12 और 50 दुधारू पशुओं वाली डेयरी फार्म इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करके युवाओं और किसानों के लिए रोज़गार सृजन की एक योजना भी लागू की है । पिछले सात वर्षों में, इन योजनाओं के अंतर्गत, गुजरात सरकार ने गुजरात के दुग्ध उत्पादकों को ₹198.5 करोड़ की सहायता प्रदान की है ।

(घ): इन उपायों से गुजरात में दूध का प्रापण 2001-02 के लगभग 50 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 250 लाख लीटर प्रतिदिन (5 गुना) हो गया है, साथ ही डेयरी किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आई है । पिछले 15 वर्षों में किसानों को भुगतान किए जाने वाले दूध के दामों में 140% (औसत दूध प्रापण मूल्य 400 रुपये प्रति किलोग्राम वसा से बढ़कर 950 रुपये प्रति किलोग्राम वसा) की वृद्धि हुई है । इससे दुग्ध संघों की प्रशीतन क्षमता और दूध प्रापण क्षमता को बढ़ाने में उल्लेखनीय मदद मिली है ।

*****